नवसर्जन संस्कृति

TITLE CODE : UPHIN51496
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 230
दि. 21.12.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com


# सड़क सुरक्षा के लिए सीएम योगी का 4-ई मॉडल, शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर पर होगा फोकस

**– 108 और एएलएस एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम घटाने और स्कूल व भारी वाहनों की फिटनेस जांच के निर्देश**

**– वर्ष 2025 में 46 हजार से अधिक दुर्घटनाएं और 24 हजार से ज्यादा मौतें गंभीर चेतावनी**

**– एनएसएस, एनसीसी, आपदा मित्र, स्काउट गाइड और सिविल डिफेंस की भागीदारी होगी**

**– ब्लैक स्पॉट सुधार, रोड सेफ्टी ऑडिट, ओवर स्पीडिंग और लेन ड्राइविंग पर नियंत्रण के निर्देश**

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेशव्यापी 'सड़क सुरक्षा माह' आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि नए वर्ष की शुरूआत केवल औपचारिक आयोजनों से नहीं, बल्कि जनजीवन से सीधे जुड़े सड़क सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील विषय पर ठोस संकल्प, व्यापक जनभागीदारी और व्यवहार परिवर्तन के लक्ष्य के साथ होनी चाहिए। शनिवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडलायुक्तों तथा जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा अभियान किसी भी स्थिति में औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के जीवन से जुड़ा जन आंदोलन बने।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा माह को 4-ई मॉडल के आधार पर संचालित किया जाए, जिसमें शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर चारों स्तंभों पर समान रूप से और समन्वित ढंग से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को केवल नियमों की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझाना आवश्यक है कि यातायात नियमों का पालन उनके स्वयं के जीवन, उनके परिवार और समाज की सुरक्षा से सीधे जुड़ा है।

शिक्षा के माध्यम से बच्चों, युवाओं और आम नागरिकों में सही सड़क व्यवहार विकसित किया जाए, प्रवर्तन के तहत नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो, इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़कों के ब्लैक स्पॉट और क्रिटिकल पॉइंट सुधारे जाएं तथा इमरजेंसी केयर के अंतर्गत त्वरित एम्बुलेंस सेवा और बेहतर ट्रॉमा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चारों स्तंभों पर संतुलित और एकसाथ काम किए बिना सड़क दुर्घटनाओं में वास्तविक कमी संभव नहीं है।

बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया

कि वर्ष 2025 में नवंबर तक प्रदेश में कुल 46,223 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 24,776 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री ने इन आंकड़ों को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाएं केवल प्रशासनिक या तकनीकी समस्या नहीं हैं, बल्कि यह एक बड़ी सामाजिक चुनौती है।

उन्होंने कहा कि एक भी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु पूरे परिवार को जीवन भर का दर्द दे जाती है और इस पीड़ा को वही परिवार समझ सकता है। इसी दृष्टिकोण से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशीलता के साथ-साथ कठोर निर्णय लेना भी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जनवरी के पहले सप्ताह में विशेष रूप से जागरूकता पर फोकस किया जाए और सभी विभाग अपनी-अपनी तैयारियां समय से पूरी करें। प्रदेश की प्रत्येक तहसील, ब्लॉक, जिला और सभी प्रमुख मुख्यालयों पर जागरूकता संबंधी प्रचार सामग्री अनिवार्य रूप से लगाई जाए।

उन्होंने कहा कि किसी एक वास्तविक सड़क दुर्घटना के उदाहरण को सामने रखकर आमजन को यह समझाया जाए कि एक छोटी सी लापरवाही किस प्रकार पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक और प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि यह संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे कि सड़क सुरक्षा किसी और की नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन और परिवार से जुड़ा विषय है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस अभियान में राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, आपदा मित्र, स्काउट गाइड और सिविल डिफेंस जैसे संगठनों की सक्रिय और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता से ही यह अभियान वास्तविक अर्थों में जन आंदोलन बन सकेगा। जब तक समाज स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक केवल सरकारी प्रयासों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल चालान करना सड़क दुर्घटनाओं का स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि जो लोग आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने और वाहन सीज करने की स्पष्ट नियमावली तैयार कर उसका सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के मामलों में कठोरता अनिवार्य है, क्योंकि यह सीधे तौर पर लोगों की जान से जुड़ा विषय है।

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारकों पर विस्तार से चर्चा करते हुए ब्लैक स्पॉट और क्रिटिकल पॉइंट की पहचान कर उनके त्वरित और स्थायी सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क इंजीनियरिंग की कमियां, खराब साइनज, अव्यवस्थित कट, अंधे मोड़ और अनुचित स्पीड ब्रेकर दुर्घटनाओं को बढ़ाते हैं।

## राजस्थान सीएम किसान सम्मान योजना इसी महीने जारी होगी 5वीं किस्त, फटाफट पूरे कर लें ये सारे काम

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना से जुड़े 74 लाख किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार इसी महीने योजना की 5वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, 23 तारीख को सीएम भजनलाल शर्मा किस्त जारी कर सकते हैं। जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 21वीं किस्त की राशि मिली है, वे सभी इसके लिए पात्र हैं।

इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस योजना के लिए किसानों को अलग से कोई पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद 5वीं किस्त आने से पहले कुछ जरूरी काम पूरे कर लें।

## अहमदाबाद को मिली उसकी पहली 'मेक इन इंडिया' मेट्रो ट्रेन

**मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कोलकाता स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स प्लांट में गुजरात की सांस्कृतिक भावना को प्रतिबिंबित करने वाली अत्याधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक समान ट्रेन का स्वागत किया**

**यह मेट्रो ट्रेन श्रेष्ठ कोटि की फायर सेफ्टी सहित अन्य सुरक्षा सुविधाओं तथा ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 (जीओए4) के अंतर्गत पूर्णतः ऑटोमेटेड-ड्राइवरलेस ट्रेन के रूप में कार्य करने में सक्षम है**

गांधीनगर,20 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद शहर को उसकी प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित ह्यमेक इन इंडिया' मेट्रो ट्रेन की भेंट दी।

श्री पटेल ने कोलकाता के निकट टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के आधुनिक प्लांट का दौरा कर अहमदाबाद मेट्रो रेल के कोचेस लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ह्यमेक इन इंडिया' तथा आत्मनिर्भर भारत को गति देने वाला यह महत्वपूर्ण कदम गुजरात के लिए गौरव समान है।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा उसके फैसिलिटी प्लांट में यह ट्रेन मेक इन इंडिया अंतर्गत स्वदेशी रूप से बनाई जा रही है। आधुनिक मेट्रो तथा यात्री कोच के उत्पादन के लिए सक्षम यह प्लांट अत्याधुनिक एवं आधुनिक तकनीक तथा साधन-सामग्री के साथ स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीटागढ़ प्लांट में देश के अनेक राज्यों के लोग कार्यरत हैं। यह भी एक भारत-श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री का मंत्र चरितार्थ करता है।

## राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने संबोधित किया

**उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में पीएससी की भूमिका को रेखांकित किया**

**विकसित भारत के लिए लोक सेवाओं की गुणवत्ता निर्णायक : उपराष्ट्रपति**

**योग्यता केवल बरकरार ही नहीं रखी जानी चाहिए, बल्कि इसे बरकरार रखा जाना दिखना भी चाहिए: उपराष्ट्रपति**

(जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया और भारत की शासन प्रणाली की गुणवत्ता, ईमानदारी और प्रभावशीलता को आकार देने में लोक सेवा आयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया ।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह भारत विकसित भारत@2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है,ऐसे में शासन की गुणवत्ता, और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण संस्थानों को चलाने वाले लोगों की गुणवत्ता निर्णायक सिद्ध होगी। उन्होंने लोक सेवा आयोगों को संवैधानिक संस्थाएँ करार दिया, जिन्हें देश की सेवा करने के लिए योग्य, निष्पक्ष और नैतिक लोगों को चुनने की अहम ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में प्रतिष्ठापित लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता, सरकारी भर्ती में योग्यता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। उन्होंने कहा कि दशकों से, केंद्र और राज्य स्तर पर आयोगों ने प्रशासनिक निरंतरता, संस्थागत स्थिरता और लोक सेवकों का तटस्थ चयन सुनिश्चित करते हुए जनता के भरोसे को मजबूत किया है।

लोक सेवाओं के संबंध में बदलती मांगों पर जोर देते हुए उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि डिजिटल शासन, सामाजिक समावेशन, अवसंरचना विकास, जलवायु कार्रवाई और आर्थिक परिवर्तन जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करना आज चुने गए प्रशासनिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

नैतिक मानकों के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि निष्पक्षता सरकारी भर्ती का नैतिक आधार है और भेदभाव खत्म करने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि छोटी-मोटी गड़बड़ियाँ भी संस्थानों की विश्वसनीयता कम कर सकती हैं, और उन्होंने सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी को कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि आज प्रभावशाली शासन के लिए शैक्षणिक दक्षता के साथ-साथ मजबूत नैतिक फैसले, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व व क्षमता और टीमवर्क वाले लोक सेवकों की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि लोक सेवा आयोग ज्ञान पर आधारित परीक्षाओं के साथ-साथ व्यवहार और नैतिक योग्यता के निष्पक्ष और सुनियोजित आकलन की संभावनाओं के बारे में विचार कर सकते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि केवल भर्ती आजीवन बेहतरीन कार्य किया जाना सुनिश्चित नहीं कर सकती, श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि संस्थागत ईमानदारी बनाए रखने के लिए प्रदर्शन का आकलन, सतर्कता एवं निगरानी और समय-समय पर समीक्षा करने के तरीकों को बिना किसी भेदभाव के तथा पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चरित्र और नैतिक व्यवहार राष्ट्र निर्माण और जनता के भरोसे की बुनियाद हैं।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोक सेवा आयोगों को प्रतिभा मानचित्रण और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिभा सेतु जैसी पहल सहित नवोन्मेषी तरीके तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि सही प्रतिभा को सही भूमिका मिल सके।

## राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कल्याण और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 18 दिसंबर 2025 को अल्पसंख्यक दिवस मनाया। इस अवसर पर छह अल्पसंख्यक समुदायों – मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी (जोरोस्ट्रियन) के समुदायिक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए।

माउंट कार्मेल स्कूल के अतिथि वक्ता डॉ. माइकल वी. विलियम्स ने सभा को याद दिलाया कि अल्पसंख्यक दिवस क्यों महत्वपूर्ण है, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में ईसाई समुदाय के लंबे और मौन योगदान को रेखांकित किया – ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सांप्रदायिक सीमाओं से कहीं आगे बढ़कर सेवा करती हैं।

जामिया हमदर्द के मोहम्मद तौहीद आलम ने 'सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास' के व्यापक ढांचे के भीतर अल्पसंख्यक कल्याण पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि आज के शासन का मूल आधार समावेश है। खालसा कॉलेज के प्रोफेसर हरबंस सिंह ने गुरुबानी से प्रेरणा लेते हुए समझाया कि सहअस्तित्व और सामूहिक समृद्धि केवल नारे नहीं बल्कि जीवंत परंपराएं हैं।

आचार्य येशी फुंटसोक और डॉ. इंदु जैन ने बौद्ध और जैन समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से उचित समाधान की मांग की। अनुभवी पारसी नेता श्री मराजबान नरीमन जैवाला ने अल्पसंख्यक-केंद्रित कार्यक्रमों और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका का विस्तार से वर्णन करते हुए अपने संबोधन का समापन किया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत के विभिन्न समुदायों को एक साझा नागरिक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत-जी राम जी विधेयक को रेखांकित करने वाला एक लेख साझा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का एक लेख साझा किया है, जिसमें विकसित भारत-जी राम जी विधेयक के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है।

लेख में बताया गया है कि विकसित भारत-जी राम जी विधेयक रोजगार गारंटी को बढ़ाकर, स्थानीय नियोजन को लागू करके, श्रमिक सुरक्षा एवं कृषि उत्पादकता के बीच संतुलन बनाकर, योजनाओं को एकीकृत करके, अग्रिम पंक्ति की क्षमता को मजबूत कर शासन व्यवस्था का आधुनिकीकरण करके ग्रामीण आजीविका में परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखता है। लेख में यह भी कहा गया है कि यह विधेयक सामाजिक सुरक्षा से पीछे हटना नहीं बल्कि उसका नवीनीकरण है।

# केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह में भागीदारी की

**चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण, समृद्धि और ग्रामीण विकास के प्रतीक थेः श्री शिवराज सिंह चौहान**

**'विकसित भारत-जी राम जीः से ग्रामीण रोजगार और विकास की नई तस्वीर बनेगी- श्री चौहान**

**'विकसित भारत-जी राम जीः में किसान और श्रमिकों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयासः श्री चौहान**

**सिर्फ मिट्टी खोदने के काम से रोजगार गारंटी की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती थी- श्री केंद्रीय मंत्री श्री चौहान**

**नए कानून के जरिए स्कूल, नाली, सड़क, पुलिया यहां तक की खेत की सड़क बनाने का काम भी किया जाएगा- श्री चौहान**

**प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वैज्ञानिक सीधे खेतों में जाकर किसानों से संवाद करे रहे हैं- केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान**

**नेतृत्व में गरीब कल्याण और विकास का काम करते रहेंगे- श्री शिवराज सिंह**

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में किसान ट्रस्ट द्वारा पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने पुस्तक का भी विमोचन किया तथा प्रगतिशील किसान और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संस्थानों को सम्मानित किया। समारोह में शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

# भोपाल में आज उत्तर-मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की तीसरी क्षेत्रीय बैठक आयोजित हुई

**भारत विकसित@2047 तब होगा जब हर घर, गांव, शहर और राज्य विकसित और आत्मनिर्भर होगा: श्री मनोहर लाल**

(जीएनएस)। माननीय केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शहरी विकास मंत्रियों की तीसरी क्षेत्रीय बैठक 20 दिसंबर, 2025 को भोपाल में आयोजित की गई।

नई दिल्ली में 17 जुलाई, 2025 को शहरी विकास मंत्रियों की राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित हुई जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर इस परामर्श की नींव रखी गई। बेंगलुरु में 30 अक्टूबर, 2025 और हैदराबाद में 18 नवंबर, 2025 को आयोजित पहली और दूसरी क्षेत्रीय बैठकों के अनुरूप, विचार-विमर्श, शहरी विकास के प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित थे ताकि सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

इस बैठक में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के माननीय शहरी विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश की माननीय शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा बागड़ी, छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं शहरी प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साओ, राजस्थान के माननीय शहरी विकास एवं स्थानीय स्वशासन विकास राज्य मंत्री श्री झबर सिंह खर्रा, उत्तर प्रदेश के माननीय शहरी विकास, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन एवं ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश के माननीय शहरी विकास राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर और




संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग के सहयोग से इस क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उत्तर मध्य राज्यों, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सहित शहरी विकास मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आए।

अपने आरंभिक भाषण में माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित हो जाएगा, जब हर घर, गांव, शहर और राज्य विकसित और आत्मनिर्भर होगा। माननीय केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 टूलकिट जारी किया। सरल, सुविधाजनक और प्रभावी नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सात आईटी प्लेटफॉर्म के वीडियो का शुभारंभ भी किया।

माननीय केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न केंद्रीय मिशनों की प्रगति की समीक्षा की।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत, माननीय मंत्री जी ने डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (डीआरएपी) के ढांचे के अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व द्वारा डंपसाइटों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें सुधार प्रयासों में तेजी लाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी भागीदार राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे मेंटर और मेंटी शहरों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से स्वच्छ शहर जोड़ी (एसएसजे) के तहत तैयार की गई कार्य योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन करें।

अटल पुनर्जीवन एवं शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) के अंतर्गत, माननीय मंत्री जी ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, शहरी जल एवं स्वच्छता संसाधनों की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करने तथा उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को अधिकतम करने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी भागीदार राज्यों से परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने, समन्वय बढ़ाने और नल जल आपूर्ति एवं सीवरेज कवरेज में संतृप्ति प्राप्त करने का आग्रह किया गया।

'सभी के लिए आवास' अभियान के अंतर्गत माननीय केंद्रीय मंत्री ने निमार्णाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के घरों के निर्माण को पूरा करने और पीएमएवाई-2.0 के घरों की नींव रखने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को एएचपी (सभी के लिए आवास) घरों में अधिभोग सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को गृह ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इस उद्देश्य के लिए, अंगीकार अभियान मार्च 2026 तक जारी रहेगा और पीएमएवाई लाभार्थियों को विभिन्न लाभों का एकीकरण करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।

पीएम-ईबस सेवा योजना से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ मेट्रो नेटवर्क के सघनीकरण और शहरी परिवहन के अंतर्गत फर्स्ट-लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर चर्चा की गई।

राज्य मंत्रियों ने क्षेत्रीय परामर्शों के माध्यम से राज्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से जुड़ने के लिए गृह मंत्रालय (एमओएचयूए) के दृष्टिकोण की सराहना की। भारत के शहरी परिवर्तन की यात्रा को गति देने के लिए साझा प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय अवसरों की पहचान करने और सहकर्मी सीखने के लिए सुधार के रास्ते तय करने के लिए देश के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाएंगी।

माननीय केंद्रीय मंत्री ने नई मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी की।

# संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने अमरावती में वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय में आंध्र प्रदेश के पहले जेनरेशन-जेड परिवर्तित परिसर डाकघर का उद्घाटन किया

(जीएनएस)। ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने कैंपस डाकघरों के आधुनिकीकरण और उन्हें छात्र-केंद्रित सेवा केंद्रों में बदलने की राष्ट्रव्यापी पहल के अंतर्गत, जेनरेशन-जेड विषय पर आधारित वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय उप डाकघर का अमरावती स्थित वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय परिसर में आज उद्घाटन किया ।

उद्घाटन समारोह में आंध्र प्रदेश सर्कल की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल सुश्री बीपी श्रीदेवी, आईपीओएस; वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी. अरुलमोलीवरमन; गुंटूर जिले की कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती ए. थमीम अनासरिया, आईएएस; वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. जगदीश चंद्र मुदिगंती; विजयवाड़ा क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल डॉ. वेन्नम उपेंद्र, आईपीओएस; आंध्र प्रदेश सर्कल के महाप्रबंधक (वित्त) श्री के. विनोद कुमार, आईपी एंड टीएएफएस;







और लेखा निदेशक श्री अभिलाष पासम, सहित कई गणमान्य व्यक्ति, वरिष्ठ अधिकारी और संकाय सदस्य उपस्थित थे।

यह पहल भारत डाक अभियान के एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है जो युवा भारत से जुड़ती है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती और कैंपस परिवेश के भीतर आधुनिक, सुलभ सेवाएं प्रदान करती है।

यह पहल इंडिया पोस्ट के परिवर्तन के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक डाकघरों को समकालीन, भविष्य के लिए तैयार संस्थानों के रूप में पुनर्परिभाषित करना और युवा पीढ़ी के साथ जुड़ाव को मजबूत करना है। नए सिरे से तैयार किए गए डाकघर को सोच-समझकर जेनरेशन-जेड की सोच के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जिसमें कार्यक्षमता, रचनात्मकता, नवाचार और आधुनिक सौंदर्यशास्त्र का संयोजन है।

जेनरेशन-जेड विशेष पर आधारित इस डाकघर में नई पीढ़ी की सुविधाएं जैसे दीवारों पर भारतीय डाक से जुड़े साहित्य का प्रदर्शन , कॉफी की सुविधा, फुटबॉल टेबल, मुफ्त वाई-फाई, पत्रिकाएं और उन्नत डिजिटल सेवा उपलब्ध हैं, जो इसे एक स्वागत योग्य और छात्र-अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने "वीआईटीः आंध्र प्रदेश का जेनरेशन-जेड थीम वाला डाकघर" शीर्षक से एक विशेष डाक कवर भी जारी किया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा कि यह पहल डाक विभाग की डाकघरों को युवा नागरिकों की बदलती आकांक्षाओं के अनुरूप जीवंत सेवा केंद्रों में बदलने की प्रतिबद्धता को दशार्ती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी पहल छात्रों को आवश्यक डाक, वित्तीय और डिजिटल सेवाओं से सुलभ और रुचिकर तरीके से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विशेष रूप से जेनरेशन-जेड उपयोगकर्ताओं के लिए परिकल्पित, कैंपस डाकघर सरलीकृत सेवा वितरण, डिजिटल भुगतान विकल्प और डाक, बैंकिंग और बीमा सेवाओं तक एक ही छत के नीचे निर्बाध पहुंच प्रदान करता है। यह पहल नवाचार, समावेशिता और ग्राहक-केंद्रित सेवा वितरण पर भारतीय डाक के लक्ष्य को सुदृढ़ करती है और छात्रों के बीच वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देती है।

# कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इस दिन बिहार आ रहे हैं नितिन नबीन

(जीएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आगामी 23 दिसंबर को पहली बार पटना आ रहे हैं। उनके इस पहले बिहार आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा में भारी उत्साह है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि बांकीपुर के विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन का स्वागत किसी उत्सव से कम नहीं होगा।

पूरे पटना को सजाया जा रहा है और कार्यकताओं के साथ-साथ आम जनता भी उनके अभिनंदन के लिए तैयार है। यह दौरा बिहार भाजपा के लिए संगठन और सरकार के बीच नए समन्वय की शुरूआत माना जा रहा है।

जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू

नितिन नवीन के पटना आगमन को लेकर भाजपा कार्यकताओं ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के अनुसार, 23 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे उनके हवाई अड्डे पर उतरते ही भव्य स्वागत किया जाएगा। पटना की सड़कों को होर्डिंग्स और



झंडों से पाट दिया गया है। बांकीपुर से विधायक होने के नाते स्थानीय जनता में भी अपने नेता के राष्ट्रीय कद बढ़ने को लेकर जबरदस्त गौरव का भाव है, जिसे यादगार बनाने के लिए पूरा शहर सज-धज कर तैयार है।

पंचमुखी हनुमान मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

नितिन नवीन का रोड शो पटना हवाई अड्डे से शुरू होकर शेखपुरा और राजवंशी नगर पहुंचेगा, जहां वे पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद उनका काफिला पुनाईचक होते हुए हाई कोर्ट पहुंचेगा। वहां वे संविधान निमार्ता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके उपरांत, वे आयकर गोलंबर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण (खढ) की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इन प्रतीकात्मक कार्यों के जरिए भाजपा अपने वैचारिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संदेश जनता तक पहुंचाना चाहती है।

मिलर हाई स्कूल में ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह

नितिन नवीन के स्वागत समारोह का मुख्य केंद्र ऐतिहासिक मिलर हाई स्कूल का मैदान होगा। यहां बिहार भाजपा की ओर से एक विशाल अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य भर से हजारों कार्यकताओं के जुटने की संभावना है। इस समारोह के माध्यम से भाजपा अपनी सांगठनिक एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन कार्यकताओं को संबोधित करेंगे, जिससे आगामी चुनावों और संगठन विस्तार को लेकर नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।

# चौथी मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक, 23 लाख से ज्यादा अभिभावकों की भागीदारी

(जीएनएस)। पंजाब की भगवंत मान सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में अहम सुधार के काम चल रहे हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक शनिवार (20 दिसंबर) को आयोजित की गई थी। यह चौथी पैरंट-टीचर मीटिंग है, जिसमें 23.30 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बालिकाएं), श्री आनंदपुर साहिब में पीटीएम कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं 'आप' पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने जिला होशियारपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल पददी सूरा सिंह में मेगा पीटीएम में हिस्सा लिया।

विधायकों और अधिकारियों ने 7500 से अधिक स्कूलों का दौरा किया

इस बैठक के संबंध में विधायकों, स्कूल शिक्षा सचिव श्रीमती अनिंदिता मित्रा, एस.सी.ई.आर.टी. की निदेशक किरण शर्मा, उपायुक्तों और शिक्षा विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने 7500 से अधिक स्कूलों का दौरा किया। शिक्षा मंत्री बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पंजाब सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से 'मां-पिता की भागीदारी' (अभिभावकों की साझेदारी) की थीम के तहत अभिभावकों और स्कूलों के बीच संबंधों को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बड़े स्तर की पहल अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदार बनाकर विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों को



बेहतर बनाने के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दिखाती है।

मेगा कार्यशाला के लिए 40,000 शिक्षकों को दी गई ट्रेनिंग

शिक्षा मंत्री ने बताया कि अभिभावक कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। 40,000 से अधिक शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। हरेक सरकारी स्कूल से कम से कम एक शिक्षक को इसमें शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत जहां प्रशिक्षित शिक्षक संवाद सत्रों का संचालन करते हैं, वहीं एसएमसी सदस्य अभिभावकों के साथ समन्वय और अन्य सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के शैक्षणिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता हेतु अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

प्री-प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के बच्चों के अभिभावकों ने लिया हिस्सा

उन्होंने कहा कि इस पहल के अंतर्गत प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1-1.5 घंटे की अभिभावक कार्यशाला के बाद मेगा पीटीएम को साझा कार्यशाला डिजाइन और एसएमसी-नेतृत्व वाली बैठक योजनाओं के माध्यम से लागू किया जाता है। अभिभावकों को जानकारी के लिए हैंडआउट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशालाओं का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका को सुदृढ़ करना, घर और स्कूल में सक्रिय व सकारात्मक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, समग्र बाल विकास के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के बीच मजबूत सहयोग सुनिश्चित करना है।

पंजाब की अअढ सरकार ने शहीदी सभा के लिए फतेहगढ़ साहिब में करवाए ये खास इंतजाम, उट भगवंत मान ने दी हर डिटेल

पंजाब की अअढ सरकार ने शहीदी सभा के लिए फतेहगढ़ साहिब में करवाए ये खास इंतजाम, उट भगवंत मान ने दी हर डिटेल

उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जिम्मेदारियों की साझा समझ विकसित करते हुए अभिभावकों और स्कूलों के बीच मजबूत आपसी संबंध सुनिश्चित करती है। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। यह पहल घर और स्कूल के बीच तालमेल को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिससे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन, नियमित उपस्थिति और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभिभावक-शिक्षक बैठक के दौरान संवाद विद्यार्थियों के प्रयासों और अभिभावकों के सहयोग की सराहना से शुरू होता है। इससे बातचीत के लिए सकारात्मक और सम्मानजनक आधार सुनिश्चित होता है। इस प्रक्रिया से बच्चों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, क्योंकि संवाद के दौरान शिक्षक और अभिभावक विद्यार्थियों की रुचियों, आकांक्षाओं और शैक्षणिक प्रगति पर विस्तार से चर्चा करते हैं तथा एक-दूसरे से फीडबैक लेते हैं।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह की एक नई पहल है, जिसके माध्यम से अभिभावकों को शैक्षणिक लक्ष्यों और शिक्षा क्षेत्र में आगामी पहलों की स्पष्ट जानकारी मिलती है। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि वे घर पर बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं।

# मोटापे का इलाज शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता; भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाएं, वजन घटाने वाली दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करें: डॉ. जितेंद्र सिंह

**मंत्री महोदय ने दो दिवसीय "एशिया ओशिनिया कॉनफ्रेंस ऑन ऑबेसिटी" (एओसीओ) के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, इसमें डॉ. क्यौंग कोन किम, डॉ. वोल्कान युमुक, डॉ. महेंद्र नरवारिया और अन्य सहित इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख विशेषज्ञों ने भाग लिया; मंत्री महोदय ने कहा कि मोटापा एक गंभीर समस्या है जिसे केवल डॉक्टर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता; हर नागरिक की इसमें भूमिका है**

**भारत में 63% मौतें गैर-संक्रामक रोगों से जुड़ी हैं जो किसी न किसी रूप में मोटापे से संबंधित हैं; अब समाज में जागरूकता का समय आ गया है- डॉ. जितेंद्र सिंह**

**फिट इंडिया, खेलो इंडिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आहार पर ध्यान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता को दशार्ता है**

(जीएनएस)। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि वर्तमान में उपलब्ध वजन घटाने वाली या मोटापा कम करने वाली दवाओं का उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

मंत्री जी, जो स्वयं एक प्रख्यात मधुमेह विशेषज्ञ और चिकित्सा के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि मोटापा एक जटिल, दीर्घकालिक और बार-




बार होने वाला विकार है, न कि केवल एक सौंदर्य संबंधी या जीवनशैली से जुड़ी चिंता। उन्होंने भारत की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक के रूप में उभरी इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समग्र समाज के दृष्टिकोण का आह्वान किया।

डॉ. क्यौंग कोन किम, डॉ. वोल्कान युमुक, डॉ. महेंद्र नरवारिया, डॉ. बीएम मक्कर, डॉ. बंशी साबू और अन्य सहित क्षेत्र के कुछ प्रमुख विशेषज्ञों की उपस्थिति में आयोजित दो दिवसीय "एशिया ओशिनिया कॉनफ्रेंस ऑन ऑबेसिटी" (एओसीओ) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों, शोधकताओं, नीति निमार्ताओं और अन्य हितधारकों का एक मंच पर एकत्रित होना ही भारत में मोटापे की महामारी की बढ़ती गंभीरता को दशार्ता है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र इतना गंभीर विषय है कि इसे केवल एक अर्थशास्त्री के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, उसी प्रकार मोटापा भी इतना गंभीर विषय है कि इसे केवल एक चिकित्सक या महामारी विज्ञानी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इसकी गहरी सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जड़ें हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में गैर-संक्रामक रोगों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है जो किसी न किसी रूप में मोटापे से जुड़े हैं और इनका कुल मृत्यु दर में लगभग 63 प्रतिशत का योगदान है। उन्होंने बताया कि टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्थितियां मोटापे से जुड़ी हैं, जिनमें केंद्रीय या आंतरिक मोटापा भी शामिल है, जो विशेष रूप से भारतीयों में प्रचलित है और शरीर के कुल वजन से परे भी स्वतंत्र स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि भारतीय संदर्भ में किसी प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय मंचों से बार-बार मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बारे में बोलना अभूतपूर्व है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खान-पान की आदतों और दैनिक दिनचर्या में छोटे, निरंतर बदलावों पर प्रधानमंत्री का बल मोटापे को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। यह फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसी पहलों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 से स्वास्थ्य राष्ट्रीय नीति निर्माण के केंद्र में आ गया है और सरकार रोकथाम, किफायती और शीघ्र जांच पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत, व्यापक जांच कार्यक्रमों और स्वदेशी टीकों के विकास सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को इस बदलाव के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने आयुष मंत्रालय के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को एकीकृत करने पर सरकार के जोर का भी उल्‍लेख किया।

मंत्री जी ने मोटापे की रोकथाम से जुड़े बढ़ते व्यवसायीकरण और भ्रामक सूचनाओं के प्रति आगाह किया और चेतावनी दी कि अवैज्ञानिक दावे और तथाकथित त्वरित समाधान अक्सर लोगों को गुमराह करते हैं और उन्हें प्रमाण-आधारित देखभाल से दूर करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल औपचारिक अनुमोदन ही नैदानिक अभ्यास में पूरी सच्चाई नहीं बताते, और याद दिलाया कि कैसे पूर्व के दशकों में रिफाइंड तेलों के व्यापक उपयोग से अनपेक्षित दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम सामने आए। जनहित की रक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने मिथकों और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से आधुनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के जिम्मेदार उपयोग के माध्यम से निरंतर प्रयासों का आह्वान किया।

युवा पीढ़ी तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जन जागरूकता को चिकित्सा सम्मेलनों और विशेषज्ञ चचाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमें न केवल जानकार लोगों से बात करनी चाहिए, बल्कि उन लोगों से भी बात करनी चाहिए जो यह नहीं जानते कि वे नहीं जानते।" उन्होंने आगे कहा कि 2047 तक एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत के युवाओं के स्वास्थ्य और ऊर्जा की रक्षा करना आवश्यक है।

# केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल मेट्रो का उद्घाटन किया

**भोपाल भारत का 26वां शहर बन गया जहां मेट्रो नेटवर्क संचालित हो रहा है;**

**भारत की कुल संचालित मेट्रो लंबाई 1,090 किमी पहुंच गई**

प्रविष्टि तिथिः 20 ऊएउ 2025 7:06ढट‸८ ढक्ह ऊॅ‘

भोपाल में मेट्रो सेवाओं की शुरूआत के साथ भारत की शहरी परिवहन यात्रा में एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। भोपाल के शामिल होने के साथ, देश भर में 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं अब संचालित हो रही हैं, जिससे भारत में कुल संचालित मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 1,090 किमी हो गई है।

भोपाल मेट्रो मध्य प्रदेश की राजधानी शहर के लिए एक बड़ा कदम है, जो नागरिकों के लिए शहरी यात्रा को तेज, स्वच्छ और अधिक सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित यह परियोजना स्मार्ट, हरित और टिकाऊ गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है।



भोपाल मेट्रो की कुल लंबाई 30.8 किमी है, जिसमें दो कॉरिडोर और एक डिपो शामिल हैं:

ऑरेंज लाइनः 16.74 किमी

ब्लू लाइनः 14.16 किमी

शहर के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए डिजाइन की गई यह मेट्रो ट्रैफिक जाम को कम करने और निवासियों के समग्र जीवन स्तर को इससे बेहतर बनाने की उम्मीद है।

प्राथमिकता कॉरिडोर का उद्घाटन

भोपाल मेट्रो के पहले चरण, ऑरेंज लाइन प्राथमिकता कॉरिडोर का आज उद्घाटन किया गया। लगभग 7 किमी लंबे इस प्राथमिकता खंड में आठ ऊंचे स्टेशन शामिल हैं: AIIMS, अलकापुरी, DRM ऑफिस, रानी कमलापति, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केंद्रीय विद्यालय और सुभाष नगर।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

# सम्पादकीय

## 'विकसित भारत' की तरफ अग्रसर देश में भी विदेशी जीवन के चमक की ललक

आज की भारतीय युवा पीढ़ी इतिहास के निर्णायक संक्रमण काल में खड़ी है। एक ओर विदेशी जीवन की झिलमिलाती चमक, उच्च वेतन, बहुराष्ट्रीय वंपनियों की प्रतिष्ठा तथा तथाकथित ह्यग्लोबल लाइफस्टाइल' उसे लुभा रही है; दूसरी ओर स्वदेश की माटी की खुशबू, पारिवारिक प्यार, समाज का अपनापन तथा राष्ट्र-दायित्व की मौन पुकार जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान कर रही है। यह द्वंद्व केवल रोजगार या करियर का नहीं, अपितु आत्म-पहचान, सांस्वृतिक स्वाभिमान तथा राष्ट्र-भविष्य से जुड़ा गहन विमर्श है। युवाओं को निर्णय लेते समय यह ध्यान रखना होगा कि भारत अब अवसर-विहीन देश नहीं; विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है तथा 'विकसित भारत' के लक्ष्य हेतु संकल्पबद्ध है।आरबीआई आंकड़ों के अनुसार, बीते वर्षो में लाखों युवा पेशेवर विदेश गये, कितु ह्यरिवर्स ब्रेन ड्रेन' की प्रवृत्ति भी उभर रही है। जब अपने ही देश में अवसरों का विस्तार हो रहा है, तब विदेश-आकर्षण का रहस्य क्या है? आधुनिक भारत तकनीक, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, फार्मा, वृषि-प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, हस्तशिल्प, अंतरिक्ष तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक वेंद्र बन रहा है। टाटा, रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, महिद्रा जैसी वंपनियाँ तथा नवरत्न संस्थान बौद्धिक क्षमता, नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बने हुए हैं। इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी, एचएएल, सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएमआर, आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी तथा एम्स जैसे संस्थान अंतरिक्ष, रक्षा, चिकित्सा तथा विज्ञान में राष्ट्र-निर्माण को सशत्त कर रहे हैं।चंद्रयान-तीन की सफलता, एक साथ कई उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता, रक्षा में स्वदेशीकरण, डिजिटल इंडिया का समावेशन, 1.2 लाख स्टार्टअप्स (100ऋ् यूनिकॉर्न सहित), मेक इन इंडिया तथा नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति प्रमाणित करते हैं कि भारत अब अवसरों का निर्यातक बन चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने शिक्षा-शोध-नवाचार को नई दिशा दी है। नैस्कॉम रिपोर्ट्स के अनुसार, टियर-दो, तीन शहरों में लगभग चालीस प्रतिशत नई नौकरियाँ सृजित हो रही हैं तथा सरकारी योजनाएँ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण और त्रण प्रदान कर रही हैं। फिर भी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया आदि की ओर युवाओं का रुझान तथा माता पिता की इच्छा बनी हुई है। शायद बेहतर वेतन, जीवन-शैली तथा वैश्विक अनुभव के कारण। सोशल मीडिया, ओटीटी तथा पॉप-संस्वृति ने योजनाबद्ध तरीके से विदेश विशेष कर पमि को सफलता का पर्याय गढ़ा है।कितु भारतीय युवाओं को यह भी जानना होगा कि विदेशों में महँगाई, एकाकीपन, सांस्वृतिक दूरी, नस्लीय भेदभाव तथा मानसिक तनाव जैसे कठोर यथार्थ भी छिपे हैं।

# अटल नेतृत्व, अविरत विकास : सुशासन से महिला सशक्तिकरण

- राज्य में लखपति दीदी तथा नमो ड्रोन दीदी योजना से महिलाएँ बनीं आत्मनिर्भर
- दो वर्ष में राज्य में लखपति दीदी की संख्या 5.96 लाख के पार, गाँव में रहने वालीं महिलाओं के सपने हो रहे हैं साकार
- कंकुबेन ने कच्छी हस्तकला उत्पादों की बिक्री से वार्षिक दस लाख रुपए से अधिक की कमाई की, अब ऑनलाइन साइट्स पर भी बिक्री
- प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात ने नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अनेक सफल आयाम अपनाए हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, 20 दिसंबर : सुशासन द्वारा राज्य के नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत रही है। सुदूरवर्ती नागरिकों तक विकास पहुँचाने तथा महिलाओं को सशक्त बनाकर भारत की विकास यात्रा में जोड़ने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में ह्यलखपति दीदी' योजना शुरू की गई थी। 2027 तक 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का इस योजना का उद्देश्य है। गुजरात की महिलाओं को इस योजना का व्यापक लाभ मिले; इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में व्यापक प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप दिसंबर 2025 तक राज्य में लगभग 5 लाख 96 हजार महिलाओं की आय एक लाख रुपए से अधिक तक पहुँची है और वे गर्व के साथ गुजरात की ह्यलखपति दीदी' बनी हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने





कहा है, 'प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात ने नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अनेक सफल आयाम अपनाए हैं। लखपति दीदी योजना के सफल क्रियान्वयन से गुजरात आगामी समय में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए तैयार है ह्व

**कच्छ की कंकुबेन गर्वा की वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक**

लखपति दीदी कार्यक्रम को राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। कच्छ में भुज तहसील के मानकुवा गाँव में रहने वालीं कंकुबेन गर्वा का परिवार परंपरागत रूप से हस्तकला से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ह्यसरस मेला' में शामिल होकर उनके कच्छी हस्तकला उत्पाद लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके बाद उन्होंने 1.5 लाख रुपए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से तथा 4 लाख रुपए के क्रेडिट कैश लोन द्वारा गाँव में ही दुकान शुरू की और स्वयं-सहायता समूह की अन्य महिलाओं को जोड़कर उत्पादन बढ़ाना शुरू किया। आज उनके उत्पाद राज्य के बाहर भी पहुँचे हैं। वे एमेजोन जैसी विख्यात ऑनलाइन साइट्स पर भी बिक्री कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही हैं। हाल में वे वार्षिक 10 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित कर रही हैं और उनके कहे अनुसार उनकी इस सफलता में राज्य सरकार की ओर से लाइवलीहुड मिशन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

**नमो ड्रोन दीदी योजना से भावनाबेन को मिली नई पहचान**

बनासकाँठा में काँकरेज तहसील के वरसाडा की निवासी भावनाबेन भरतकुमार चौधरी ने ड्रोन दीदी बनकर आसपास के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बीए तक पढ़ाई की है और वे पशुपालन-खेती के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत ड्रोन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव करने के प्रशिक्षण के लिए उनका चयन होने के बाद वे काँकरेज तहसील में ड्रोन दीदी के रूप में जानी जाती हैं। वे गाँव में रहकर अपने सपने साकार कर रही हैं और आसपास की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि कक्षा 10 उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता के साथ 18 से 60 वर्ष आयु समूह की महिलाएँ नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत ड्रोन पायलट बन सकती हैं।

**राज्य में 10 लाख से अधिक संभावित लखपति दीदी की पहचान**

राज्य के प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) द्वारा हाल में 10.74 लाख महिलाओं की पहचान की गई है, जो लखपति दीदी बन सकती हैं। चिह्नित की गई संभावित लखपति दीदी की मौजूदा गतिविधियों तथा उनके पास उपलब्ध स्रोतों, हुए खर्च और आय का विवरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल आजीविका रजिस्टर तैयार किया गया है। इस रजिस्टर से प्राप्त जानकारी के आधार पर चिह्नित की गईं लखपति दीदी को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण, एसेट, आर्थिक सहायता तथा मार्केटिंग के लिए आवश्यक सपोर्ट किया जा रहा है।

**कैसे काम करती है लखपति दीदी योजना ?**

यह योजना स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहायक बनती है, जिससे उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक हो सके। महिलाएँ कृषि, पशुपालन, हस्तकला तथा अन्य स्थानीय क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता तथा बाजार से कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाती है, जिससे उनकी आय बढ़ सके। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लखपति दीदी के लिए निम्न विवरण अनुसार आय की गणना की जाती है :

- कृषि एवं सम्बद्ध व्यवसाय की कुल वार्षिक आय।
- नॉन-फार्म एक्टिविटी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज आदि की आय।
- परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी करता हो, तो उसकी आय।
- फार्म तथा नॉन-फार्म व्यवसाय में मजदूरी कार्य से प्राप्त आय।
- सरकार के योजनागत लाभ द्वारा प्राप्त राशि।
- कमिशन, मानद् वेतन से प्राप्त आय।

**248 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 10 हजार से अधिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण**

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गुजरात सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तहसील स्तर पर 248 मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति की गई है, जिन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षण दिया है। ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सहयोग देंगे। इस समग्र प्रक्रिया के लिए डिजिटल आजीविका रजिस्टर पर डेटा अपडेट किया जाता है, जो देखरेख के साथ महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग एवं मार्केट कनेक्टिविटी देने में सहायक होता है।

# शुभमन गिल को वर्ल्ड कप टीम से निकालने के पीछे गौतम गंभीर और अगरकर? लखनऊ में हुई पूरी प्लानिंग

(जीएनएस)।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई (इउउक) सचिव देवजीत सैकिया ने टीम का ऐलान शनिवार को किया। इस स्क्वॉड में वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को शामिल नहीं किया गया है। यह फैसला फैंस के लिए हैरान करने वाला रहा है। सोशल मीडिया पर वह ट्रेंड कर रहे हैं। अब उन्हें टीम से निकाले जाने के पीछे की कहानी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी-20 सीरीज के दौरान ही यह फैसला हो गया था। इस बारे में किसी ने भी प्रिंस से बात नहीं की थी। शुभमन गिल को टी20 टीम से बाहर किए जाने की कोई आधिकारिक जानकारी पहले नहीं दी गई थी। उनसे इस बारे में बात भी नहीं की गई और सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

एनडीटीवी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इउउकसे जुड़े एक सूत्र ने भी इसकी पुष्टि की है। सूत्र के मुताबिक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की शुभमन गिल को स्क्वॉड से बाहर करने के बारे में चर्चा हुई थी। यह फैसला लखनऊ में हुआ था, जहां टीम इंडिया टी-20 मैच खेलने पहुंची थी। हालांकि, प्रदूषण की वजह से मैच रद्द हो गया था। इसके बावजूद किसी ने भी शुभमन



गिल को पहले से इसकी जानकारी नहीं है। उन्हें सीधे टी20 स्क्वाड से बाहर कर दिया गया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूर्यकुमार यादव खुद खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद उनका कप्तानी पद कम से कम टी20 वर्ल्ड कप तक सुरक्षित माना जा रहा है। मैनेजमेंट इतने अहम टूनार्मेंट से पहले कोई बड़ा बदलाव करने के पक्ष में नहीं है।

**फॉर्म और फिटनेस दोनों पर संकट**

- सूत्रों के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान शुभमन गिल को पैर में चोट लगी थी। इस चोट ने गंभीर और अगरकर की प्लानिंग को एक और मजबूत तर्क दे दिया।

- रन बनाने के लिए उनका संघर्ष चल रहा है और उस पर लगी चोट से मामला और गंभीर हो गया। टीम मैनेजमेंट ने उनको लगी चोट के बाद विकल्पों पर विचार करने का मन बना लिया था।

- इसमें हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर की भूमिका भी बताई जा रही है।

**अहमदाबाद ळ-20 मैच खेलना चाहते थे शुभमन गिल**

बताया जा रहा है कि शुभमन गिल अहमदाबाद में खेले गए पांचवें टी20 मुकाबले में खेलना चाहते थे। हालांकि, तब तक टीम मैनेजमेंट अपना मन बना चुका था। मैनेजमेंट उन्हें टी20 स्क्वॉड से बाहर करने का फैसला ले चुका था। गिल को बिना किसी पूर्व सूचना के टीम से ड्रॉप करने के दावे ने सनसनी मचा दी है। इससे कोच और कप्तान के साथ सेलेक्टर्स के व्यवहार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आम तौर पर फॉर्म से जूझ रहे खिलाड़ियों से टीम से निकालने से पहले बात की जााती है। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के दौर में ऐसा किया जाता था। उससे पहले दिलीप वेंगसरकर के मुख्य चयनकर्ता रहते हुए भी यह ट्रेंड था।

बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर गिल को टीम से बाहर किए जाने को लेकर कोई ठोस वजह नहीं बता पाए थे। अब चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।

# दुनिया के टॉप-5 सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से? भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी?

(जीएनएस)।

इस साल के अंत तक दुनिया में घूमने की आजादी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास किस देश का पासपोर्ट है। आज के दौर में पासपोर्ट सिर्फ पहचान का दस्तावेज नहीं, बल्कि आपकी ग्लोबल मोबिलिटी की चाबी बन चुका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक, किसी देश का पासपोर्ट जितना मजबूत होता है, उसके नागरिक उतने ही ज्यादा देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। यही वजह है कि हर साल इस रैंकिंग पर पूरी दुनिया की नजर रहती है।

**हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है?**

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया की सबसे भरोसेमंद रैंकिंग मानी जाती है, जो यह बताती है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पहले से वीजा लिए जा सकता है। इसमें केवल वही गंतव्य गिने जाते हैं, जहां वीजा-फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। जितनी ज्यादा पहुंच, उतना ही ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है।



**ीं१ एल्लीं१ 2025**

**सिंगापुर बना दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट**

2025 में भी सिंगापुर ने अपना नंबर-1 स्थान बरकरार रखा है। सिंगापुर पासपोर्ट रखने वाले लोग दुनिया के 193 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि सिंगापुर की अंतरराष्ट्रीय छवि, कूटनीतिक रिश्ते और आर्थिक ताकत कितनी मजबूत है।

**एशिया और यूरोप का दबदबा**

दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा, जिसके नागरिक 190 देशों में वीजा-मुक्त यात्रा कर सकते हैं। जापान ने 189 गंतव्यों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद यूरोप की एंट्री होती है। जर्मनी 188 देशों तक पहुंच के साथ चौथे स्थान पर रहा, जबकि इटली भी 188 गंतव्यों के साथ पांचवें पायदान पर मौजूद है। इससे साफ है कि एशिया और यूरोप अब भी ग्लोबल ट्रैवल फ्रीडम में सबसे आगे हैं।

**भारत की रैंकिंगः सुधार की गुंजाइश बाकी**

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 83वां स्थान मिला है। भारतीय पासपोर्ट धारक 57 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। भले ही यह आंकड़ा बीते सालों के मुकाबले बेहतर हुआ हो, लेकिन टॉप देशों से तुलना करें तो अभी भारत को लंबा सफर तय करना है।

**पाकिस्तान की स्थिति और भी कमजोर**

पाकिस्तान इस सूची में 102वें स्थान पर है। पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 31 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग पाकिस्तान की कमजोर कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय भरोसे की कमी को भी दशार्ती है।

**क्यों मायने रखता है मजबूत पासपोर्ट?**

मजबूत पासपोर्ट का मतलब सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और ग्लोबल एक्सपोजर के ज्यादा मौके भी होते हैं। 2025 की यह रैंकिंग साफ दिखाती है कि आने वाले समय में देशों की सॉफ्ट पावर और अंतरराष्ट्रीय रिश्ते नागरिकों की जिंदगी पर सीधा असर डालते रहेंगे।

# केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा संबंधी आधारभूत ढांचे में एक दशक की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां पिछली शताब्दी के अंत में देश में केवल एक एम्स था, वहीं आज पूरे भारत में 23 एम्स संस्थान हैं जो हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा प्रशिक्षण के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ते हैं

श्री नड्डा ने केजीएमयू के स्नातकों से उत्कृष्टता बनाए रखने और चिकित्सा शिक्षा तथा शोध में योगदान देने का आग्रह किया

एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी/एमएस, डीएम/एम.सी.एच., एमडीएस, एमएससी, नर्सिंग और संकाय श्रेणियों में उत्कृष्ट शैक्षणिक, नैदानिक और शोध उपलब्धियों के लिए 81 छात्रों और एक संकाय सदस्य को सम्मानित किया गया

प्रविष्टि तिथिः 20 ऊए 2025 4:29ढ_८ ढक्ह ऊ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के 21 वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री ब्रजेश पाठक, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज कुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह और केन्द्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद भी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए स्नातक छात्रों को बधाई दी और भारत में चिकित्सा विज्ञान शिक्षा और रोगी देखभाल को बढ़ावा देने में केजीएमयू के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, 'केजीएमयू को 2025 की एनआईआरएफ रैंकिंग में







8वां स्थान मिला है और इसके 12 संकाय सदस्यों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है ह्व

श्री नड्डा ने पिछले दशक में भारत के स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां पिछली शताब्दी के अंत में देश में केवल एक एम्स था वहीं आज पूरे भारत में 23 एम्स संस्थान हैं। यह हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा प्रशिक्षण का विस्तार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 819 हो गई है। इसी प्रकार, स्नातक मेडिकल सीटों की संख्या 51,000 से बढ़कर 1,19,000 और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या 31,000 से बढ़कर 80,000 हो गई है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निदेर्शानुसार, 2029 तक स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर 75,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, जिनमें से 23,000 से अधिक सीटें एक वर्ष में ही जोड़ी जा चुकी हैं।

श्री नड्डा ने इस बात का भी उल्लेख किया कि आज देश में 18 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं जो लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत झ पीएमजेएवाई योजना के तहत भारत की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी यानी 62 करोड़ से अधिक लोगों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 'बुनियादी शिक्षा हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा एक विशेषाधिकार है जो समाज केवल कुछ ही लोगों को प्रदान करता है ह्व उन्होंने यह उल्लेख किया कि सरकार प्रत्येक एमबीबीएस छात्र पर 30 से 35 लाख रुपये खर्च करती है और नए डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे अपने पेशेवर करियर की शुरूआत करते ही समाज के प्रति अधिक जिम्मेदारियां निभाएं।

श्री नड्डा ने अपने संबोधन के समापन में, स्नातक छात्रों से अकादमिक और शोध क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने और अपने पेशेवर और नैतिक आचरण में उत्कृष्टता के माध्यम से केजीएमयू की प्रतिष्ठित विरासत को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें आजीवन सीखने वाले और नवप्रवर्तक बने रहने, चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने और करुणा के साथ समाज की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

श्री ब्रजेश पाठक ने युवा डॉक्टरों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई देते हुए कहा कि केजीएमयू 120 वर्षों से अधिक समय से चिकित्सा शिक्षा, शोध और मानवता की सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए कहा '2017 में सरकारी क्षेत्र में केवल 17 और निजी क्षेत्र में 23 मेडिकल कॉलेज थे और आज राज्य में कुल 81 पूरी तरह से कार्यरत मेडिकल कॉलेज हो गए हैं ह्व उन्होंने आगे कहा 'आज सभी 75 जिलों में डायलिसिस और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, एनएचएम के माध्यम से 5,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, और अतिरिक्त आईसीयू बेड के माध्यम से तृतीयक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया गया है ह्व

इस अवसर पर, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी/एमएस, डीएम/एम.सी.एच., एमडीएस, एमएससी नर्सिंग और संकाय श्रेणियों में उत्कृष्ट शैक्षणिक, नैदानिक और अनुसंधान उपलब्धियों के लिए 81 छात्रों और एक संकाय सदस्य को सम्मानित किया गया। पुरस्कारों में स्वर्ण और रजत पदक, योग्यता प्रमाण पत्र, पुस्तक पुरस्कार, नकद पुरस्कार के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध और सर्वश्रेष्ठ रेजिडेंट के लिए पुरस्कार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा और संबद्ध विषयों में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक वरिष्ठ संकाय सदस्य को विशेष सम्मान से नवाजा गया।

इस कार्यक्रम में केजीएमयू की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद (पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित), केजीएमयू की डीन और विश्वविद्यालय विधानसभा एवं कार्यकारी परिषद की सदस्य प्रो. अपजीत कौर तथा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

## ईसा मसीह का कुरान में जिक्र, माना जाता है मसीहा, फिर मुस्लिम क्यों नहीं मनाते क्रिसमस? जानें

(जीएनएस)।

भर में ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भारत समेत कई देशों में यह त्योहार धार्मिक के साथ-साथ सामाजिक उत्सव का रूप भी ले चुका है। ऐसे में हर साल यह सवाल उठता है कि जब कुरान में ईसा मसीह का जिक्र कई बार आता है, उन्हें एक महान पैगंबर माना गया है, तो फिर मुस्लिम समुदाय क्रिसमस क्यों नहीं मनाता।

इस्लाम में ईसा मसीह को ईसा अलैहि सलाम कहा जाता है। कुरान में उनका नाम और उनसे जुड़ी घटनाएं लगभग 35 बार आती हैं। मुस्लिम मान्यता के मुताबिक ईसा मसीह अल्लाह के भेजे गए बड़े पैगंबरों में से एक हैं। उनका जन्म एक चमत्कार माना जाता है और उनकी मां मरियम को भी इस्लाम में बेहद पवित्र स्थान प्राप्त है। हालांकि, इस्लाम ईसा मसीह को पैगंबर मानता है, लेकिन उन्हें ईश्वर या ईश्वर का पुत्र नहीं मानता। यही सबसे बड़ा धार्मिक अंतर है।

इस्लाम में ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह के भेजे गए महान पैगंबरों में शामिल किया जाता है। कुरान उन्हें पैगंबर मोहम्मद से पहले आने वाले एक अहम संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत करता है।

दिलचस्प बात यह है कि कुरान में ईसा का जिक्र पैगंबर मोहम्मद से भी ज्यादा बार हुआ है। कुरान में कम से कम 35 बार उनका जिक्र मिलता है, जिनमें 27 बार ईसा या यीशु के नाम से और 8 बार "मसीहा" के रूप में उनका उल्लेख किया गया है।

मुसलमान और ईसाई, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि ईसा का जन्म असाधारण था। इस्लामी मान्यता के मुताबिक मरियम ने अल्लाह के हुक्म से बिना पिता के ईसा को जन्म दिया। इसे उसी तरह का चमत्कार माना जाता है, जैसे आदम को बिना माता-पिता के पैदा किया गया था। इस्लाम के मुताबिक ईसा ने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का संदेश दिया, ठीक वैसे ही जैसे उनसे पहले और बाद में आने वाले सभी पैगंबरों ने किया।

हालांकि, ईसा के अंत को लेकर दोनों धर्मों की मान्यताएं अलग हैं। ईसाई मानते हैं कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, जबकि इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने ईसा को बचा लिया था और उन्हें स्वर्ग बुला लिया। मुसलमान यह भी मानते हैं कि कयामत से पहले ईसा मसीह दोबारा धरती पर लौटेंगे। यही विश्वास ईसाई धर्म में भी मिलता है, जहां उनकी वापसी को दुनिया के अंत से जुड़ा एक बड़ा संकेत माना जाता है।

क्रिसमस ईसाई धर्म में ईसा मसीह के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ईसाई मान्यता के मुताबिक ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और इसी विश्वास के साथ यह पर्व जुड़ा हुआ है। इस्लाम में इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया जाता। इस्लाम की बुनियाद इस विश्वास पर टिकी है कि अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए कई पैगंबर भेजे और सभी पर ईमान लाना जरूरी है। इसी वजह से मुसलमान ईसा अलैहि सलाम को भी दिल से मानते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। इसके बावजूद मुसलमान क्रिसमस नहीं मनाते, क्योंकि इस त्योहार से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं इस्लाम की शिक्षाओं से मेल नहीं खातीं।

# विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : मुख्यमंत्री

## जनता दर्शन में आई शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय। ऐसे एजेंटों से पीड़ितों का पूरा पैसा भी वापस कराया जाय। उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड करने वालों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 250 लोगों से

मुलाकात की। सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का प्रभावी निराकरण कराया जाएगा। जनता दर्शन में आई एक महिला ने परिवार के एक सदस्य को विदेश भेजने के नाम पर एजेंट द्वारा ठगी किए जाने का मामला मुख्यमंत्री को बताया। इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित का पैसा दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला को भी समझाते हुए कहा, विदेश जाने के नाम पर एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गलत तरीके से जाने पर लोगों को वहां जेल में रहना पड़ सकता है। जनता दर्शन में आए पुलिस से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पीड़ितो की मदद में विलंब और लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। हर पीड़ित की त्वरित मदद की जाए। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधिसम्मत कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध करा दें। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को प्यार-दुलारकर सीएम योगी ने उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हुए चॉकलेट दिया।

# सो रहे एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। सफदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीगंज चौराहे पर स्थित मकान के बरामदे मे सो रहे एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सूचना पर पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मृतक वृद्ध काफी दिनों से बीमार बताया जा रहा है ।

सफदरगंज बदोसराय मार्ग पर स्थित रानीगंज मे एक पुराने विवादित बाड़े मे अपने परिजनों के साथ रह रहे 70 वर्षीय वृद्ध ओमप्रकाश पुत्र शंभूदयाल बीती रात्रि बरामदे मे सो रहे थे शनिवार की सुबह जब लोगो ने देखा तो वृद्ध ओमप्रकाश मृत अवस्था मे पड़े थे मृतक की बहू शालिनी निगम की सूचना पर पहुंची सफदरगंज पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बताते चले कि ग्राम पंचायत सफदरगंज के पूर्व प्रधान स्वर्गीय मोहनलाल अवस्थी का वर्षो पुराना बाड़ा है कुछ दिन वर्ष पहले इसी पुराने बाड़े मे एग्रो का कार्यालय संचालित था पूर्व प्रधान स्वर्गीय मोहनलाल अवस्थी के पोते राज मोहन अवस्थी परिवार के साथ के साथ लखनऊ मे रहते है मृतक ओमप्रकाश निगम की कुछ जमीन का हिस्सा इस बाड़े से मिला था जिसको लेकर ओमप्रकाश ने पूरे बाड़े मे रहने लगे जिसका विवाद चल रहा था बीती रात्रि वृद्ध बरामदे मे सो रहे थे जो काफी दिनों से बीमार भी थे जिनकी मृत्यु हो गयी । थानाध्यक्ष अमर चौरसिया ने बताया कि सूचना पर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ।

# भाजपा नेता कस्बा शाहबपुर निवासी शशि भुर्जी के भतीजे की इलाज के दौरान मौत

(जीएनएस)।

मसौली, बाराबंकी। एक सप्ताह पूर्व अज्ञात वाहन की चपेट मे आने से बुरी तरह घायल हुए भाजपा नेता कस्बा शाहबपुर निवासी शशि भुर्जी के भतीजे की इलाज के दौरान मौत हो गयी।

थाना क्षेत्र के कस्बा शहाबपुर निवासी भाजपा नेता शशी भुर्जी के 22 वर्षीय भतीजे नितिन गुप्ता का 12 दिसंबर को लखनऊ में जिम जाते समय रात्रि में शहीद पथ के सम्मिट बिल्डिंग के पास किसी वाहन से एक्सीडेंट हो गया था।जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।

डायल 112 ने जांच पड़ताल कर परिजनों को सूचित किया तो परिजनों ने इलाज के लिए हिन्द मेडिकल इंस्टिट्यूट सफेदाबाद में एडमिट कराया। स्वास्थ्य लाभ होने के बाद अपने घर लेकर चले आये थे।लेकिन कल अचानक तबीयत बिगड़ने पर पुनः हिन्द मेडिकल इंस्टिट्यूट सफेदाबाद में एडमिट कराया।जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक दो भाइयों में नितिन सबसे बड़ा था। मौत की खबर सुनकर पूरे कस्बे के लोग स्तब्ध होकर गमगीन हो गये। परिवार पर दुःखो का पहाड़ टूट पड़ा।मृतक का अंतिम संस्कार पैतृक निवास पर किया गया।

# जिलाधिकारी ने बिलासपुर गौशाला का निरीक्षण किया, गौवंश को सर्दी से बचाव एवं चारा-पानी की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए

(जीएनएस)।

पीलीभीत। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने शनिवार को तहसील अमरिया की ग्राम पंचायत बिलासपुर स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौवंश की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को सर्दी के मौसम में पशुओं को ठंड से बचाने तथा चारा व पानी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने गौशाला प्रबंधन से गौवंशों की संख्या, स्वास्थ्य स्थिति और दैनिक जरूरतों की जानकारी ली। उन्होंने पाया कि कुछ पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, इसलिए तत्काल कदम उठाने को कहा। चारा की

गुणवत्ता व पानी की शुद्धता पर विशेष जोर देते हुए, उन्होंने नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के आदेश दिए। डीएम ने कहा कि गौवंश संरक्षण जिले की प्राथमिकता है, और किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

तहसीलदार व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशाला में स्वच्छता बनाए रखने और पशुओं के लिए दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

# करछना पावर प्रोजेक्ट के नाम से अधिग्रहित भूमि काश्तकारों को वापस करने के संबंध में ज्ञापन

(जीएनएस)। प्रयागराज

शुक्रवार को प्रयागराज समाज उत्थान समिति कचरी करछना प्रयागराज के प्रबंधक समाज सेवक डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल के नेतृत्व में जिलाधिकारी प्रयागराज के नाम सम्बोधित ज्ञापन एडीएम सिटी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्याम बिहारी को तहसील करछना जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में करछना पावर प्रोजेक्ट के नाम से अधिग्रहित भूमि काश्तकारों को वापस करने के संबंध में का ज्ञापन समस्त भूमि अधिग्रहित क्षेत्र के ग्राम प्रधानों व काश्तकारों के हस्ताक्षर युक्त दिया गया।सविनय निवेदन है कि प्रयागराज समाज उत्थान समिति कचरी करछना

प्रयागराज के संरक्षक शिव बहादुर पटेल व प्रबंधक डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल के नेतृत्व में 19 अक्टूबर 2025 को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें किसानों के द्वारा निम्न बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपने की बात कही गई जो इस प्रकार हैं:

1 यह कि हम काश्तकारों का कथन है कि 18 वर्ष पूर्व अधिग्रहित की गई उक्त जमीन व भूमि पर कोई पावर प्लांट का कार्य नहीं किया गया ना ही काश्तकारों की जमीन वापस की गई।2 हम काश्तकारों का कथन है कि अगर भूमि वापस न की जाए तो नए सिरे से भूमि का अधिग्रहण किसानों की सहमति से पुनः किया जाए।

3 हम काश्तकारों का कथन है कि नए सिरे से अधिक अधिग्रहित भूमि का नए सर्किल रेट से प्रतिकर दिया जाए।

4 हम काश्तकारों का कथन है कि अधिग्रहित भूमि यदि वापस नहीं की गई और ना ही पावर प्लांट लगाया गया तो किसानों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

5 हम काश्तकारों का कथन है कि अधिग्रहित भूमि के आसपास गांव की भूमि जो अधिग्रहित नहीं है उसको आवारा जानवर नीलगाय बन सुअरा शाही आदि जंगली जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं जिसके कारण किसान पीड़ित एवं ग्रसित है।

6 हम काश्तकारों का कथन है कि अधिग्रहित भूमि पर पावर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त अन्य कोई योजना का कार्य नहीं किया जाए उक्त में संबंधित काश्तकारों या उनके आश्रित बच्चों को रोजगार हेतु सम्मिलित किया जाए।

7 हम काश्तकारों का कथन है कि पावर प्रोजेक्ट स्थापित हो जाने के बाद शासनादेशानुसार काश्तकारों को समस्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। ज्ञापन सौंपने वालों में समाज सेवक डॉक्टर कुल भूषण सिंह पटेल,पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष करछना कृष्ण मुरारी पांडेय, ग्राम पंचायत सदस्य कटका भूपेन्द्र प्रसाद पांडेय आदि कृषक शामिल रहे। आयुक्त प्रयागराज को भी लिखित ज्ञापन दिया गया माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदि को भी ज्ञापन की प्रति दी जाएगी।

# हरे-भरे शीशम के पेड़ों पर ठेकेदार का चला आरा, प्रतिबंधित वृक्ष काटने का मामला वायरल

(जीएनएस)।

शाहजहांपुर।थाना खुटार क्षेत्र के हरनाई गांव में ठेकेदार की मनमानी से हरे-भरे शीशम के पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। वन विभाग के प्रतिबंध के बावजूद 8 पेड़ों को काटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ठेकेदार ने बिना अनुमति के आरा चलाया, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पेड़ पूरी तरह हरे-भरे थे, जो वन संरक्षण कानून के तहत कटाई पर प्रतिबंधित हैं। ग्रामीणों ने बताया

कि इससे इलाके का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा, और ठेकेदार ने स्थानीय अधिकारियों को भी लापरवाह रखा।

शाहजहांपुर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी हैं।

# मेयर ने व्यापारियों के धरना-प्रदर्शन स्थल पर उनकी समस्या सुनकर उन्हें दिया आश्वासन

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने कल नगर निगम मुख्यालय पर लखनऊ व्यापार मंडल एवं व्यापारी भाइयों द्वारा किए जा रहे धरने में सम्मिलित होकर उनकी समस्याओं एवं मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना व्यापारी ने नगर निगम द्वारा प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क वृद्धि पर अपना विरोध दर्ज कराया तथा इस संबंध में ज्ञापन सौंपा उन्हें आश्वस्त किया गया कि किसी भी स्थिति में व्यापारी भाइयों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ने दिया जाएगा इस विषय पर संबंधित अधिकारियों एवं माननीय सदन में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा मेयर के आश्वासन के पश्चात व्यापारी भाइयों ने अपना धरना शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त किया नगर

निगम सदैव व्यापारियों के हितों के प्रति संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है।

# जनपद न्यायाधीश के द्वारा कारागार का किया निरीक्षण

**बन्दियों से की वार्ता, जानी समस्याऐं एवं बंदियों की समस्याओं का निस्तारण करने के दिये निर्देश।**

(जीएनएस)।

पीलीभीत 20 दिसम्बर 2025/ जनपद न्यायाधीश श्री रविन्द्र कुमार चतुर्थ, जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मा0 न्यायाधीश

द्वारा कारागार में बन्दियों के किशोर/पुरूष बैरक, महिला बैरक सहित अन्य बैरकों, भोजनालय, अस्पताल एवं लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। मा0 जनपद न्यायाधीश द्वारा बैरक के निरीक्षण के दौरान बंदियों से बातचीत करते हुये उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

मा0 जनपद न्यायाधीश द्वारा अस्पताल निरीक्षण के दौरान बीमार बंदियों से बातचीत करते हुये उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई और वहां उपस्थित डॉक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि बीमार बंदियों की स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि मानक के अनुरूप बंदियों को सुविधायें उपलब्ध कराई जाये। निरीक्षण के दौरान मा0 जनपद न्यायाधीश द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था देखी गई और निर्देशित किया कि निर्धारित मानकों के अनुरूप बंदियों को भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। बंदियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिन बंदियों के पास जमानत हेतु वकील नही है उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनकी जमानत हेतु वकील उपलब्ध कराये जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कारागार की साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज श्री सुनील कुमार पूर्णकालिक सचिव/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मंगल देव सिंह, जेल अधीक्षक, जेलर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

# डफरिन अस्पताल में इलाज के नाम पर वसूली का आरोप, वीडियो वायरल

(जीएनएस)। लखनऊ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ क्षेत्र के वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय (डफरिन हॉस्पिटल) में तीमारदारों से पैसे लेकर इलाज कराए जाने का सनसनीखेज मामला आया सामने आपको बताते चलें की अस्पताल परिसर में तैनात गार्ड द्वारा कथित अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल इस वायरल वीडियो में इलाज के नाम पर मरीजों के तीमारदारों से पैसे लेने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि बिना भुगतान के मरीजों को जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रहीं और इलाज में जानबूझकर देरी की जा रही है मामले के सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज के दावों की पोल खुलने से आम लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

# भारत के पुल : कठिनाइयों पर स्थापत्य की विजय

(जीएनएस)।

बलखाती नदियों, गहरी खाइयों और बेचैन समंदरों के ऊपर तने भारत के पुल इंजीनियरी में देश की महत्वाकांक्षाओं के मूक साक्षी हैं। ये सिर्फ शहरों और क्षेत्रों को ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को भी जोड़ते हैं। ये इनमें से हर पुल अपने में साहसिक डिजाइन तथा निर्मम मौसम और मुश्किल भूभागों पर विजय पाने के मानवीय संकल्प की कहानी समेटे है।

भारत की संयोजकता को परिभाषित करने वाले पुल

अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु

पुल अक्सर उन स्थानों को एक दूसरे से मिलाते हैं जिन्हें भूगोल ने लंबे समय से अलग-थलग कर रखा था। समूचे भारत में पुल जिस तरह रोजमर्रा की जिंदगी को संवारते हैं उस ओर हममें से ज्यादातर का ध्यान नहीं जाता। वे उन दूरियों को घटाते हैं जिन्हें तय करने में कई दिन लग जाते थे। वे दूरदराज के समुदायों तक पहुंच बनाते और प्रकृति के सबसे उग्र रूपों का सामना करते हैं। देश भर में फैले अनगिनत पुलों के जाल में कई प्रमुख पुल विशालता और भारतीय अवसंरचना की दृष्टि की मिसाल हैं।

अरब सागर के ऊपर अटल सेतु मुंबई महानगर के कैनवस पर कूची के बिंदास स्पर्श की तरह है। इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) के नाम से भी जाना जाता है। यह भीड़भाड़ और समय के बंधनों से मुक्त क्षितिज की ओर मुंबई का सबसे बड़ा कदम है। इसे मुंबई के द्वीपीय शहर पर ट्रैफिक के भारी बोझ को घटाने के लिए विकसित किया गया है। आधुनिक निर्माण और सुरक्षा प्रणालियों के इस्तेमाल से बना यह पुल खाड़ी के आरपार ज्यादा तेज और सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। इससे कनेक्टिविटी को बढ़ा कर स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान कर रहा है। यह पुल समंदर के ऊपर 16.5 किलोमीटर और जमीन पर 5.5 किमी है। इस परियोजना के लिए 17843 करोड़ रुपए की लागत मंजूर की गई थी और यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। कोविड 19 की वैश्विक महामारी से पैदा अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद यह परियोजना पटरी पर रही और निर्धारित समय पर पूरी हुई।

चेनाब पुल

विश्व के सबसे ऊंचे मेहराबदार दुर्घटना के जोखिम में गिरावट आने के साथ ही यात्रियों के रोजाना यात्रा के अनुभव में सुधार आता है। लेकिन इसका प्रभाव परिवहन से आगे भी है। एमटीएचएल मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायक है। यह व्यापार और उद्योग के लिए रेल सेतु, चेनाब पुल का निर्माण पूरा होने के साथ ही भारत का इंजीनियरी कौशल भी एक नई ऊंचाई को छू रहा है। इस परियोजना को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। दुर्गम इलाके, हद से ज्यादा खराब मौसम और पर्वतों से गिरते पत्थरों ने निर्माण का काम बेहद कठिन बना दिया था। 4 लाखों लोग एफिल टॉवर को देखने के लिए पेरिस जाते हैं। लेकिन चेनाब पुल उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। यह महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक संपत्ति होने के साथ ही उभरता पर्यटन स्थल भी है। चेनाब नदी के 359 मीटर ऊपर बना यह पुल उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लिंक (यूएसबीआरएल) का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस रेल मार्ग पर वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है जिससे श्रीनगर और कटरा के बीच यात्रा का समय घट कर सिर्फ लगभग 3 घंटों का रह जाएगा।